(ग) क्या यह सच है कि सरकार की इन योजनाओं के लाभ छोटे किसानों तक नहीं पहुंच रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने प्लान योजना बनाई है जिसमें मुख्यतया छोटे और सीमान्त किसानों को कृषि औजारों पर सब्सिडी दी जाती है। ये योजनाएं हैं :—

(1) विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम गेहूं।

(2) विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम मक्का और कदन्न।

(3) विशेष पटसन विकास कार्यक्रम।

(4) एकीकृत चावल विकास कार्यक्रम।

(5) गहन कपास विकास कार्यक्रम।

(6) तिलहन उत्पादन कार्यक्रम।

(7) राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम।

(8) कृषि में प्लास्टिक का उपयोग (ड्रिप-सिंचाई)।

(9) कृषि मशीनीकरण का प्रबंधन अभिज्ञात उन्नत यंत्रों, पादप रक्षण उपस्कर, स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई उपस्करों, पावर टिलर और छोटे ट्रैक्टरों पर सब्सिडी उपलब्ध है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में गन्ना खरीद केन्द्रों की स्थापना

1568. **श्री रामसिंह राठवा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों को गन्ने का उचित मूल्य दिलाने और उन्हें नकद भुगतान करने हेतु गुजरात में कितने गन्ना खरीद केन्द्रों की स्थापना की गई है;

(ख) इस समय गन्ने के मूल्य किस आधार पर तय किए जाते हैं; और

(ग) किसानों को तत्काल भुगतान किए जाने संबंधी दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन न किए जाने के कारण क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) गन्ने का सांविधिकन्यूनतम मूल्य निर्धारित करते समय इसकी उत्पादन लागत वैकल्पिक फसलों से कृषक को होने वाली आय; कृषि जिन्सों के मूल्यों के सामान्य रुख, उपभोक्ता को उचित दर पर चीनी की उपलब्धता, चीनी उत्पादकों द्वारा गन्ने से निकली गई चीनी का बिक्री मूल्य और गन्ने से निकाली चीनी की मात्रा का समुचित ध्यान रखा जाता है।

(ग) गन्ना उत्पादकों को देय गन्ने की कीमतों की अदायगी सही समय पर कराने की जिम्मेदारी प्रथमतः राज्य सरकारों की है जिनके पास ऐसी अदायगी सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक शक्तियों और संगठन मौजूद होते हैं। ऐसी अदायगियों के निपटान के लिए केन्द्रीय सरकार, अपनी ओर से, राज्य सरकारों को आवश्यक उपाय करने के लिए समय-समय पर सलाह देती है।

Scheme For Famine Prone Areas in Rajasthan

1569. SHRI AJIT P. K. JOGI : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether a scheme of Rs. 194 crores has been sent to the Central Government by the Government of Rajasthan for the implementation in famine prone areas;

(b) if so, the details thereof and action taken thereon;